Implementation of 20-Point Programme

1290. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of PROGRAMME IMPLEMENTATION be pleased to state.

(a) whether it is a fact that considerable shortfall in the achievement of targets set for some of the major components of the 20-Point Programme during 1985-86 has been reported;

(b) if so, which are these areas and the shortfall in the targets achieved for the 20-Point Programme;

(c) the States which have shown unsatisfactory performance in the implementation of the programmes and the reasons therefor; and

(d) the steps Government propose to take to accelerate the process of implementation of the Programme?

THE MINISTER OF PROGRAMME IMPLEMENTATION (SHRI A. B. A. GHANI KHAN CHOUDHURY): (a) and (b) No, Sir. A statement giving the percentage achievement for the year 1985-86 in respect of the points/items covered in the Monthly Progress Report is attached. [*See* Appendix CXXXVIII, Annexure No. 37]. Only in respect of 3 items viz. Integrated Rural Development Programme (Item No. 3-A), Bonded Labour Rehabilitation (Item No. 6) and Sub-Centres (Item No. 14-B) the performance is rated as 'Poor i.e. below 30 per cent of the target.

(c) The following States, in overall ranking registered less than 80 per cent achievement: Assam, Bihar, Jammu & Kashmir, Kerala Manipur, Meghalaya, Nagaland, Orissa, Tripura and West Bengal. Major reasons for the shortfall are: (i) inadequate infrastructural facilities and administrative arrangements, (ii) difficulties in regard to land acquisition including forest land, (iii) shortage of funds, (iv) shortage of construction material and (v) difficulties in the identification of old beneficiaries for second dose of assistance, etc.

(d) From time to time, Government of India takes up the matter with the States for speedy implementation of the programme.

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के श्री मनोहर सिंह को स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन में कटौती

1291. **श्री शिव कुमार मिश्र :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि श्री मनोहर सिंह, पुत्र श्री ऊधब सिंह निवासी रुद्रपुर, थाना जलीपुर जनपद शाहजहांपुर को उत्तर प्रदेश को स्वतंत्रता सेनानी योजना 1972 के के तहत केन्द्रीय राजस्व से पेंशन मंजीकृत हुई थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनता पार्टी शासन काल में इनके मामले की पुनः जांच कराई गई और उनकी वार्षिक आय 5000/— रु० से अधिक घोषित की गई थी और उनकी पेंशन बन्द करने का नोटिस दिया गया था ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि कांग्रेस शासन के दौरान श्री मनोहर सिंह के आवेदन पर दुबारा विचार किया गया और उनकी वार्षिक आय 5000/— रु० से कम आंकी गई थी और यदि हां, तो अब तक उनकी पेंशन में से कितनी कटौती हो चुकी है और क्या अब भी 100/— रु० मासिक की कटौती की जा रही है, यदि हां, तो क्या भविष्य में यह कटौती बन्द की जाएगी तथा काटी गई धनराशि वापस की जाएगी और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) स्वीकृत पेंशन की राशि को 1-10-1976 से 135 रु० से बढ़ाकर 200 रु० करने के सम्बन्ध में 1979 में इस मामले की समीक्षा की गयी थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसम्बर, 1980 तथा अगस्त, 1981 के अपने पत्रों द्वारा सूचित किया कि वर्ष 1972 से 1980 तक के लिये श्री मनोहर सिंह की वार्षिक आय 5000 रुपये से अधिक है इसलिये श्री मनोहर सिंह